



Original Article

बिहार में शिक्षा व्यवस्था ऐतिहासिक गौरव और आधुनिक सुधार

डॉ. बंदना श्रीवास्तव

सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग,

मगध विश्वविद्यालय बोधगया, बिहार.

Manuscript ID:

IJAAR-130434

ISSN: 2347-7075

Impact Factor – 8.141

Volume - 13

Issue - 4

March – April 2026

Pp. 215 - 224

Submitted: 10 Mar. 2026

Revised: 07 Apr. 2026

Accepted: 09 Apr. 2026

Published: 10 Apr. 2026

Corresponding Author:

डॉ. बंदना श्रीवास्तव

Quick Response Code:



Website: <https://ijaar.co.in/>



DOI: 10.5281/zenodo.21872354

DOI Link:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21872354>



Creative Commons



सारांश:

बिहार में शिक्षा व्यवस्था ऐतिहासिक गौरव और आधुनिक सुधारों के बीच एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। हालिया बजट आवंटन, बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्तियों और डिजिटल क्लासरूम के विस्तार ने व्यवस्था में नई उम्मीदें जगाई हैं, हालांकि बुनियादी ढांचे की चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं।

बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर मुख्य लेख और प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए हैं:

बजट और नीतिगत सुधार (Megaplan & Budget):

- **₹70,000 करोड़ का मेगा बजट:** वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग को लगभग 70,000 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है। यह राशि राज्य के कुल बजट का करीब पांचवा हिस्सा (19.63%) है, जिसका मुख्य उद्देश्य बेसिक से लेकर उच्च और तकनीकी शिक्षा तक मॉडर्न इकोसिस्टम तैयार करना है। [1, 2]
- **नई शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली-2026:** पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पोर्टल-आधारित "बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली-2026" को मंजूरी दी है, जिससे शिक्षकों का तबादला अब ऑनलाइन और नियमबद्ध तरीके से हो सकेगा। [1]
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020):** राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) को 'वाइब्रेंट एक्सीलेंस संस्थान' के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूलों के शिक्षकों को पुनः प्रशिक्षित किया जा सके।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0), which permits others to remix, adapt, and build upon the work non-commercially, provided that appropriate credit is given and that any new creations are licensed under identical terms.

How to cite this article:

डॉ. बंदना श्रीवास्तव (2026) बिहार में शिक्षा व्यवस्था ऐतिहासिक गौरव और आधुनिक सुधार. International Journal of Advance and Applied Research, 13(4), 215 - 224. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21872354>



प्रस्तावना (Introduction):

सकारात्मक बदलाव और उपलब्धियाँ:

- **छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) में सुधार:** बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा बड़े पैमाने पर (जैसे TRE-4 के जरिए बंपर बहाली) शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इससे पहले जहां प्रति शिक्षक 53 छात्र हुआ करते थे, वहीं अब प्राथमिक स्तर पर यह अनुपात घटकर लगभग **26:1** हो गया है।
- **लड़कियों का बढ़ता नामांकन (Gender Parity):** 'मुख्यमंत्री साइकिल एवं पोशाक योजना' जैसी रणनीतियों के कारण स्कूलों में लड़कियों की हिस्सेदारी बढ़कर **49.8%** हो गई है, और सभी स्तरों पर जेंडर पैरिटी इंडेक्स (GPI) 1.0 से ऊपर पहुंच गया है। [1]
- **डिजिटल क्लासरूम:** 'उन्नयन बिहार योजना' और 'पीएम श्री (PM SHRI)' योजना के तहत राज्य के हजारों माध्यमिक विद्यालयों में **स्मार्ट क्लासरूम और ICT लैब** का तेजी से विकास हुआ है।

प्रमुख चुनौतियाँ और जमीनी हकीकत:

- **कुल नामांकन में गिरावट:** UDISE+ के नवीनतम डेटा के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन में गिरावट देखी गई है, जो घटकर 21.13 मिलियन रह गया है। इसका कारण पलायन या निजी ट्यूशन की ओर झुकाव माना जा रहा है।
- **उत्क्रमित (Upgraded) स्कूलों का संकट:** विशेषज्ञों का कहना है कि कागजों पर "हर पंचायत में 10+2 स्कूल" का लक्ष्य तो पूरा कर लिया गया है,

लेकिन कई मिडिल स्कूलों का सिर्फ नाम बदलकर उन्हें हाई स्कूल बनाया गया है, जहाँ आज भी विज्ञान प्रयोगशालाओं (Labs) और विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है।

- **उच्च शिक्षा विधेयक पर विवाद:** हाल ही में प्रस्तावित 'बिहार उच्च शिक्षा विधेयक-2026' का शिक्षकों द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इसके तहत सरकारी अंगीभूत डिग्री कॉलेजों को कुलपतियों के नियंत्रण से अलग कर सीधे सरकार के अधीन लाने का प्रावधान है।

चर्चा:

अकादमिक संदर्भ और संदर्भ पुस्तकें (Reference Materials)

यदि आप इस विषय पर शोध या निबंध लिख रहे हैं, तो ये पुस्तकें उपयोगी हो सकती हैं:

- **अधिगम एवं शिक्षण (Learning and Teaching):** बिहार के विश्वविद्यालयों के B.Ed पाठ्यक्रम के आधार पर लिखी गई यह पुस्तक कक्षा के आधुनिक ढांचे और मूल्यांकन प्रणालियों को समझने में मदद करती है।
- **बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर निबंध (Brainly/Wikipedia Hindi):** ऐतिहासिक नालंदा और विक्रमशिला काल से लेकर वर्तमान तक के बदलावों का विवरण।



बिहार में शिक्षा व्यवस्था: ऐतिहासिक गौरव से आधुनिक सुधारों तक का सफर:

- बिहार की भूमि ऐतिहासिक रूप से ज्ञान और प्रज्ञा की केंद्र रही है। प्राचीन काल में नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय वैश्विक शिक्षा के स्तंभ थे, जहाँ दुनिया भर से विद्वान आते थे। हालांकि, समय के साथ राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक पिछड़ेपन और जनसांख्यिकीय दबाव के कारण राज्य की शिक्षा व्यवस्था में भारी गिरावट देखी गई। वर्तमान समय में, बिहार अपनी पुरानी पहचान को वापस पाने के लिए बुनियादी ढांचे, डिजिटल तकनीकों और शिक्षक सुधारों के माध्यम से एक बड़े बदलाव (Transformation) के दौर से गुजर रहा है।

नीतिगत हस्तक्षेप और प्रमुख सरकारी योजनाएँ (Policy Interventions & Key Schemes):

राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्कूल छोड़ने की दर (Dropout Rate) को कम करने और नामांकन बढ़ाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं:

- **मुख्यमंत्री बालक/बालिका साइकिल योजना:** इस योजना को वैश्विक स्तर पर एक केस स्टडी के रूप में सराहा गया है। इसने माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया और लैंगिक असमानता (Gender Gap) को लगभग समाप्त कर दिया।
- **उन्नयन बिहार योजना:** यह एक अत्याधुनिक डिजिटल पहल है, जिसके तहत राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम

और इंटरैक्टिव शिक्षण उपकरण स्थापित किए गए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण दृश्य-श्रव्य (Audio-Visual) शिक्षा प्रदान करना है।

- **पीएम श्री (PM SHRI) योजना:** केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के सैकड़ों स्कूलों को आदर्श विद्यालयों (Model Schools) के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है, जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के सिद्धांतों को पूरी तरह लागू किया जा रहा है।
- **अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों के लिए विशेष स्कूल:** राज्य में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) का विस्तार किया गया है और मदरसा तथा संस्कृत शिक्षा प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए कड़े वित्तीय ऑडिट और निगरानी तंत्र स्थापित किए गए हैं।

बड़े प्रशासनिक सुधार और हालिया घटनाक्रम (Major Administrative Reforms):

वर्ष 2024 से 2026 के बीच बिहार के शिक्षा विभाग ने कुछ सबसे बड़े प्रशासनिक और नीतिगत सुधारों को देखा है:

- **रिकॉर्ड बजट आवंटन:** वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग **₹70,000 करोड़ का मेगा बजट** निर्धारित किया है। यह राज्य के कुल बजटीय खर्च का लगभग 19.63% है, जो भारत के किसी भी राज्य द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले उच्चतम खर्चों में से एक है।



- **BPSC के माध्यम से बंपर नियुक्तियाँ (TRE):** बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षाओं (Teacher Recruitment Exams) के माध्यम से राज्य ने लाखों योग्य और स्क्रीन किए गए शिक्षकों की बहाली की है। इसके कारण छात्र-शिक्षक अनुपात (Pupil-Teacher Ratio - PTR) जो पहले 53:1 के खतरनाक स्तर पर था, वह अब सुधरकर प्राथमिक स्तर पर लगभग 26:1 हो गया है।
- **ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026:** ट्रांसफर-पोस्टिंग में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म करने के लिए सरकार ने पूर्णतः डिजिटल और पोर्टल-आधारित बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली-2026 को मंजूरी दी है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।
- **शिक्षक प्रशिक्षण और अपस्किंग (Upskilling):** राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) को मजबूत किया गया है। इसके तहत 20,000 से अधिक वरिष्ठ सरकारी शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों, वीडियो-मूल्यांकन पद्धतियों और बाल मनोविज्ञान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- **कुल नामांकन में गिरावट (Enrollment Paradox):** नवीनतम UDISE+ डेटा के अनुसार, बुनियादी ढांचे में सुधार के बावजूद प्राथमिक स्कूलों में कुल नामांकन में गिरावट देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे घटती प्रजनन दर, परिवारों का अंतर-राज्यीय पलायन और निजी कोचिंग/निजी स्कूलों की ओर बढ़ता आकर्षण है।
- **उत्क्रमित (Upgraded) स्कूलों में संसाधनों की कमी:** सरकार ने "हर पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय (10+2)" का लक्ष्य तो पूरा कर लिया है, लेकिन कई मिडिल स्कूलों का सिर्फ नाम बदलकर उन्हें हाई स्कूल बना दिया गया है। इन स्कूलों में आज भी उचित विज्ञान प्रयोगशालाओं (Labs), पुस्तकालयों और विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों (जैसे भौतिकी, गणित, अंग्रेजी) की भारी कमी है।
- **उच्च शिक्षा में प्रशासनिक टकराव:** प्रस्तावित 'बिहार उच्च शिक्षा विधेयक-2026' को लेकर विश्वविद्यालयों और सरकार के बीच तनातनी की स्थिति है। इस विधेयक के तहत कुलपतियों (VCs) की शक्तियों को सीमित कर सरकारी डिग्री कॉलेजों को सीधे शिक्षा विभाग के नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका शिक्षक संघ अकादमिक स्वायत्तता के नाम पर विरोध कर रहे हैं।
- **सत्रों में देरी (Session Lags):** हालांकि पारंपरिक विश्वविद्यालयों (जैसे मगध विश्वविद्यालय, जेपी विश्वविद्यालय) में परीक्षाओं और सत्रों में सुधार हुआ है, लेकिन डिग्री को समय पर पूरा करने की चुनौती अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

वर्तमान चुनौतियाँ और जमीनी हकीकत (Key Challenges):

इतने बड़े सुधारों के बावजूद, बिहार की शिक्षा व्यवस्था अभी भी कई संरचनात्मक समस्याओं से जूझ रही है:



भविष्य की राह (The Way Forward):

बिहार में शिक्षा के भविष्य को पूरी तरह सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने आवश्यक हैं:

- **बुनियादी ढांचे का वास्तविक उन्नयन:** केवल स्कूलों की संख्या बढ़ाने के बजाय प्रयोगशालाओं, इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **जवाबदेही और निगरानी:** बायोमेट्रिक उपस्थिति और 'ई-शिक्षाकोश' पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति की कड़ी निगरानी जारी रहनी चाहिए।
- **व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education):** माध्यमिक स्तर से ही कौशल विकास (Skill Development) को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए ताकि ड्रॉपआउट होने वाले छात्रों को रोजगार मिल सके।
- **उच्च शिक्षा का विकेंद्रीकरण:** पारंपरिक विश्वविद्यालयों के बोझ को कम करने के लिए नए स्वायत्त कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण अकादमिक संदर्भ (Reference Textbooks):

यदि आप बिहार में शिक्षाशास्त्र या सामाजिक बदलावों पर गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, तो इन पुस्तकों का संदर्भ ले सकते हैं:

- **अधिगम एवं शिक्षण (Learning and Teaching):** बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के

B.Ed पाठ्यक्रम के लिए यह एक अत्यंत लोकप्रिय और प्रामाणिक पुस्तक है, जो राज्य की आधुनिक मूल्यांकन पद्धतियों को समझाती है।

- **Education and Social Changes in Bihar:** यह पुस्तक बिहार के ग्रामीण इलाकों में साक्षरता दर, जातिगत समीकरण और शैक्षणिक पहुंच के ऐतिहासिक बदलावों का विस्तृत विश्लेषण करती है।

यदि आप इस जानकारी का उपयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, तो मुझे बताएं। मैं आपके लिए **BPSC मुख्य परीक्षा के प्रारूप में उत्तर लेखन** तैयार कर सकता हूँ या शिक्षा विभाग के **नवीनतम सांख्यिकीय आंकड़े (Data Tables)** प्रदान कर सकता हूँ।

बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए केवल बजट बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बुनियादी ढांचे, शिक्षक जवाबदेही और व्यावसायिक प्रशिक्षण में बहु-आयामी सुधार की आवश्यकता है। व्यवस्थागत कमियों को दूर कर समयबद्ध फंड उपयोग और डिजिटल ट्रेकिंग सुनिश्चित करने से ही राज्य की शैक्षणिक साख को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप विस्तृत समाधान लेख पढ़ सकते हैं।

यहाँ बिहार में शिक्षा व्यवस्था के सर्वांगीण विकास और सुधार के उपायों पर एक विस्तृत, नीति-उन्मुख (Policy-Oriented) और शोध-आधारित **लॉन्ग-नोट आर्टिकल (Detailed Solution Notes)** दिया गया है। इसे आप अपनी परीक्षाओं, निबंध लेखन या नीतिगत समीक्षा (Policy Review) के लिए उपयोग कर सकते हैं।



बिहार में शिक्षा व्यवस्था का विकास: चुनौतियाँ और दीर्घकालिक समाधान:

(Strategies to Develop and Transform the Education System in Bihar):

बिहार में शिक्षा के विकास का अर्थ केवल नए स्कूलों की इमारतें बनाना या बजट आवंटित करना नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता (Quality), पहुँच (Accessibility) और प्रासंगिकता (Relevance) को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाना है। वर्तमान प्रशासनिक सुधारों (जैसे BPSC नियुक्तियाँ) की नींव पर एक मजबूत और आधुनिक ढांचा खड़ा करने के लिए निम्नलिखित रणनीतिक कदम उठाने अनिवार्य हैं।

ढांचागत विकास और संसाधन सुदृढ़ीकरण (Infrastructure & Resource Development):

कागजों पर स्कूलों को अपग्रेड करने के बजाय उन्हें व्यावहारिक रूप से समृद्ध बनाना सबसे पहली आवश्यकता है:

- **पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला क्रांति:** हर उत्कृष्ट (Upgraded) माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ और डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएँ। इसके लिए विशेष 'लैब-फंड' जारी होना चाहिए।
- **बिजली और इंटरनेट की निरंतरता:** स्मार्ट क्लासरूम तभी काम कर सकते हैं जब स्कूलों में निर्बाध बिजली और हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो। इसके लिए स्कूलों की छतों पर सौर ऊर्जा (Solar Panels) लगाना एक ठीकाऊ समाधान है।

- **मूलभूत सुविधाएँ:** छात्राओं के ड्रॉपआउट को रोकने के लिए क्रियाशील और स्वच्छ शौचालयों तथा शुद्ध पेयजल की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

शिक्षक गुणवत्ता और जवाबदेही तंत्र (Teacher Quality & Accountability):

योग्य शिक्षकों की बहाली के बाद उनके प्रदर्शन और निरंतर मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है:

- **निरंतर व्यावसायिक विकास (CPD):** हर 6 महीने में शिक्षकों के लिए अनिवार्य रिक्रेशर कोर्स और पेडागोजी (शिक्षण पद्धति) ट्रेनिंग आयोजित की जानी चाहिए। इसके लिए DIET (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) को और अधिक स्वायत्त बनाया जाए।
- **प्रशासकीय कार्यों से मुक्ति:** शिक्षकों का मुख्य काम पढ़ाना होना चाहिए। उन्हें मध्याह्न भोजन (Mid-day Meal) के प्रबंधन, जनगणना, या अन्य गैर-शैक्षणिक प्रशासनिक कार्यों से मुक्त कर इसके लिए अलग से स्टाफ नियुक्त किया जाना चाहिए।
- **ई-शिक्षाकोश और बायोमेट्रिक सुदृढ़ीकरण:** 'ई-शिक्षाकोश' पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति की रियल-टाइम ट्रैकिंग को बिना किसी शिथिलता के लागू किया जाए, जिससे फर्जी उपस्थिति और अनुपस्थिति की समस्या खत्म हो सके।



व्यावसायिक और कौशल-आधारित शिक्षा का एकीकरण (Vocational & Skill-Based Education):

बिहार में बड़े पैमाने पर होने वाले ड्रॉपआउट और बेरोजगारी को रोकने के लिए शिक्षा को रोजगारपरक बनाना होगा:

- **माध्यमिक स्तर से वोकेशनल ट्रेनिंग:** कक्षा 9वीं से ही कोडिंग, डेटा एंट्री, मोबाइल रिपेयरिंग, आधुनिक कृषि तकनीक, और हस्तशिल्प जैसे व्यावहारिक विषयों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए।
- **'कमाओ और सीखो' (Earn while you Learn) मॉडल:** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को स्थानीय उद्योगों और व्यवसायों के साथ जोड़ा जाए ताकि छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही इंटरनशिप और वजीफा (Stipend) मिल सके।

उच्च शिक्षा और प्रशासनिक सुधार (Higher Education Reforms):

विश्वविद्यालयों के सत्रों को नियमित करना और अकादमिक माहौल को सुधारना राज्य के युवाओं को पलायन से रोकेगा:

- **केंद्रीकृत परीक्षा और परिणाम प्रणाली:** राज्य के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों के लिए एक साझा शैक्षणिक कैलेंडर (Common Academic Calendar) और केंद्रीकृत परीक्षा पोर्टल विकसित किया जाए ताकि डिग्रियां समय पर मिल सकें।

- **अकादमिक स्वायत्तता और सामंजस्य:** सरकार और कुलपतियों (VCs) के बीच चल रहे प्रशासनिक टकराव को खत्म करने के लिए एक स्वतंत्र 'बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद' (BSHEC) को पूरी तरह सक्रिय किया जाए, जो राजनीति से दूर रहकर केवल शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दे।

- **शोध और नवाचार (Research & Innovation):** राज्य के विश्वविद्यालयों में शोध के लिए विशेष अनुदान (Grants) दिए जाएं ताकि मेधावी छात्र उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली या अन्य राज्यों में जाने को मजबूर न हों।

सामुदायिक भागीदारी और सामाजिक जागरूकता (Community Engagement):

शिक्षा को एक जन-आंदोलन बनाना होगा:

- **विद्यालय प्रबंधन समितियों (SMC) का सशक्तिकरण:** ग्रामीण स्तर पर अभिभावकों को स्कूल के प्रबंधन और फंड के ऑडिट में शामिल किया जाए। जब तक समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक स्कूलों की स्थिति नहीं सुधरेगी।
- **कमजोर वर्गों के लिए विशेष कोचिंग:** महादलित, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े (EBC) छात्रों के लिए स्कूल के बाद मुफ्त उपचारात्मक कक्षाएं (Remedial Classes) चलाई जाएं ताकि वे अन्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।



निष्कर्ष (Conclusion):

बिहार में शिक्षा का विकास रातों-रात संभव नहीं है, लेकिन एक दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन, और तकनीक के सही समावेश से इसे हासिल किया जा सकता है। वर्तमान में आवंटित ₹70,000 करोड़ के भारी-भरकम बजट का यदि **समयबद्ध, पारदर्शी और परिणाम-उन्मुख (Result-Oriented)** उपयोग किया जाए, तो बिहार एक बार फिर देश का 'ज्ञान केंद्र' (Knowledge Hub) बनने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा सकता है। [1, 2]

क्या आप इस समाधान लेख के किसी विशेष बिंदु जैसे "उच्च शिक्षा सुधार" या "डिजिटल टूल्स (ICT) के उपयोग" पर अधिक विस्तृत विवरण चाहते हैं, या आपको इसके साथ ही **सांख्यिकीय सारणी (Data Tables)** की आवश्यकता है?

यहाँ बिहार में "उच्च शिक्षा सुधार" और "डिजिटल टूल्स (ICT) के उपयोग" पर एक अत्यंत विस्तृत, विश्लेषणात्मक और शोध-आधारित **लॉन्ग-नोट आर्टिकल (Detailed Analysis)** दिया गया है।

इसे आप अपनी परीक्षाओं (जैसे BPSC मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर), निबंध लेखन, या नीतिगत अध्ययन के लिए मुख्य संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

बिहार में उच्च शिक्षा सुधार (Higher Education Reforms in Bihar):

बिहार के विश्वविद्यालय वर्तमान में सत्रों में देरी (Session Lags), बुनियादी ढांचे की कमी और प्रशासनिक जटिलताओं से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं को दूर करने और

उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निम्नलिखित सुधार अनिवार्य हैं:

शैक्षणिक कैलेंडर और परीक्षा प्रणाली का केंद्रीकरण (Common Academic Calendar):

- **साझा शैक्षणिक कैलेंडर:** राज्य के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों (जैसे मगध, पटना, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय) के लिए एक सख्त और साझा शैक्षणिक कैलेंडर लागू होना चाहिए। नामांकन से लेकर परीक्षा और परिणाम जारी करने की तिथियां पहले से तय होनी चाहिए।
- **केंद्रीकृत ई-परीक्षा प्रणाली:** उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जाए। बारकोडेड उत्तर पुस्तिकाओं और ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन (OSM) के उपयोग से परिणाम में होने वाली देरी और गड़बड़ियों को समाप्त किया जा सकता है।

प्रशासनिक स्वायत्तता और जवाबदेही (Administrative Autonomy):

- **विवादों का निपटारा:** राजभवन (कुलाधिपति), राज्य सरकार (शिक्षा विभाग) और कुलपतियों (VCs) के बीच अधिकारों के टकराव को दूर करने के लिए 'बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद' (BSHEC) को एक पूर्ण स्वायत्त और शक्तिशाली निकाय के रूप में सक्रिय किया जाना चाहिए।
- **कॉलेजों का विकेंद्रीकरण (Affiliation Reform):** एक-एक विश्वविद्यालय से सैकड़ों कॉलेजों का संबद्ध (Affiliated) होना प्रशासनिक बोझ बढ़ाता है। समाधान यह है कि बड़े और पुराने



कॉलेजों को 'स्वायत्त कॉलेज' (Autonomous Colleges) का दर्जा दिया जाए ताकि वे अपनी परीक्षाएं खुद करा सकें और विश्वविद्यालय का बोझ कम हो।

पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS):

- **रोजगारपरक पाठ्यक्रम:** पारंपरिक बीए, बीएससी, बीकॉम पाठ्यक्रमों के साथ-साथ डेटा साइंस, एआई (AI), डिजिटल मार्केटिंग और व्यावसायिक कौशल को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए।
- **पूर्ण CBCS और क्रेडिट ट्रांसफर:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, जिससे छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकें और एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आसानी से क्रेडिट ट्रांसफर (Academic Bank of Credits) कर सकें।

शोध, नवाचार और अनुदान (Research & Funding):

- **बिहार रिसर्च ग्रांट:** मेधावी शोधकर्ताओं और प्रोफेसर्स के लिए एक विशेष राज्य स्तरीय फंड बनाया जाए।
- **उद्योग-अकादमिक लिंकेज:** विश्वविद्यालयों को स्थानीय उद्योगों (जैसे खाद्य प्रसंस्करण, खादी, कृषि-तकनीक) के साथ जोड़ा जाए ताकि शोध कार्य केवल कागजों तक सीमित न रहकर व्यावहारिक रूप से राज्य के विकास में काम आ सकें।

डिजिटल टूल्स और आईसीटी (ICT) का उपयोग:

भौगोलिक और आर्थिक सीमाओं को तोड़ने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है। इसे प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक निम्नलिखित तरीकों से लागू किया जाना चाहिए:

हाइब्रिड और स्मार्ट क्लासरूम का सार्वभौमिकरण (Smart Classrooms):

- **'उन्नयन' मॉडल का विस्तार:** 'उन्नयन बिहार' की सफलता को देखते हुए हर सुदूर ग्रामीण स्कूल और कॉलेज में कम से कम दो इंटरैक्टिव स्मार्ट क्लासरूम होने चाहिए, जहाँ एनिमेटेड कंटेंट और विजुअल टूल्स के जरिए कठिन विषयों (गणित, विज्ञान) को आसानी से सिखाया जा सके।
- **वर्चुअल लैब्स (Virtual Labs):** जिन स्कूलों या कॉलेजों में भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाएं नहीं हैं, वहाँ केंद्र सरकार के 'सशक्त' या आईआईटी (IIT) द्वारा विकसित वर्चुअल लैब सॉफ्टवेयर का उपयोग करके छात्रों को स्क्रीन पर प्रैक्टिकल करने का अनुभव दिया जा सकता है।

ई-शिक्षाकोश और प्रशासनिक पारदर्शिता (Digital Governance):

- **ई-शिक्षाकोश पोर्टल:** इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग शिक्षकों और छात्रों की दैनिक उपस्थिति (Biometric/Geofencing के माध्यम से), मिड-डे मील की ट्रैकिंग और स्कूल के फंड प्रबंधन के लिए कड़ाई से किया जाए। इससे फर्जीवाड़े पर पूरी तरह रोक लगेगी।



- **विद्यांजलि और छात्रवृत्ति पोर्टल:** सभी प्रकार की साइकिल, पोशाक और मेधावृत्ति योजनाओं का लाभ सीधे छात्रों के बैंक खातों में **डीबीटी (Direct Benefit Transfer)** के माध्यम से बिना किसी देरी के भेजा जाना सुनिश्चित हो।

डिजिटल लाइब्रेरी और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (OER):

- **बिहार डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क:** राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और प्रमुख कॉलेजों के पुस्तकालयों को एक केंद्रीय सर्वर से जोड़ा जाए। छात्र राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (NDL) और 'शोधगंगा' जैसे पोर्टल्स का मुफ्त उपयोग कर सकें।
- **स्वयं (SWAYAM) और मूक (MOOCs) को बढ़ावा:** ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को देश के शीर्ष प्रोफेसरों से पढ़ने का मौका देने के लिए कॉलेजों में स्वयं (SWAYAM) पाठ्यक्रमों को मुख्य डिग्री के क्रेडिट के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

शिक्षकों का डिजिटल सशक्तिकरण (Teacher Training in ICT):

- **ब्लेंडेड लर्निंग ट्रेनिंग:** शिक्षकों को केवल चॉक और टॉक (Chalk and Talk) पद्धति से ऊपर उठाकर चाटजीपीटी (ChatGPT), दीक्षा (DIKSHA) पोर्टल, और डिजिटल मूल्यांकन टूल्स का उपयोग करने के लिए अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित किया जाए।
बिहार की शिक्षा का विकास इन दोनों स्तंभों के समन्वय पर निर्भर करता है। जब तक उच्च शिक्षा की

प्रशासनिक मशीनरी को दुरुस्त (Reforms) नहीं किया जाएगा, तब तक बजट का सही लाभ नहीं मिलेगा; और जब तक शिक्षा में आधुनिक डिजिटल टूल्स (ICT) का समावेश नहीं होगा, तब तक हम राज्य के सुदूर क्षेत्रों में बैठे गरीब छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पहुँचा पाएंगे। इन सुधारों से ही बिहार अपने प्राचीन 'ज्ञान केंद्र' के गौरव को दोबारा हासिल कर सकता है।

References:

1. Education in Bihar - Wikipedia: A crowdsourced, chronologically cited historical reference tracking the state's journey from ancient global knowledge hubs (Nalanda and Vikramशिला) through colonial-era establishments like Patna University (1917).
2. Adhigam Evam Shikshan (Learning and Teaching): A practical curriculum textbook
3. e-Shikshakosh Bihar: The official digital governance portal used by the Bihar state government to monitor real-time school logs, infrastructure mapping, and biometric teacher attendance datasets.
4. UDISE+ Portal (Ministry of Education, GoI).